

उत्तर निजीकरण क्या है ।
निजीकरण का आशय सार्वजनिक क्षेत्र को संचालित एवं नियंत्रित करने के लिए निजी क्षेत्र को सम्मिलित करना है, राज्य के पब्लिस, नियमन एवं नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले उपक्रमों पर उसे शासकीय नियंत्रण को समाप्त कर उनको निजी क्षेत्र के पब्लिस एवं नियंत्रण में सौंप देना है ।
निजीकरण द्वारा निजी क्षेत्र के कार्य क्षेत्र में दायित्व में वृद्धि हो जाती है तथा राष्ट्र की प्रति भूमिका बढ़ती है ।
यह आंशिक अथवा पूर्ण निजीकरण के रूप में हो सकता है । आंशिक निजीकरण में सार्वजनिक उपक्रम पर राज्य का नियंत्रण एवं स्वामित्व विद्यमान रहता है तथा निजी क्षेत्र को सार्वजनिक उपक्रम की पूंजी, संचालन एवं लाभभागिता में एक सीमा तक अवेश दे दिया जाता है । पूर्ण निजीकरण में उपक्रम का पब्लिस एवं संचालन पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र के हस्त में चला जाता है, निजी क्षेत्र उपक्रम से सम्बन्धित योगनाओं पर स्वतंत्रा चेकर निर्णय लेता है । कुछ लोग निजीकरण को राष्ट्रीयकरण के विपरीत विचारधारा मानते हैं, परन्तु ऐसा नहीं है । राष्ट्रीयकरण में सरकार कुछ हानि का भुगतान कर उपक्रम को पूर्ण रूप से अपने स्वामित्व एवं नियंत्रण में ले लेती है, निजीकरण में निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक उपक्रम की अंश पूंजी में निवेश किया जाता है और पब्लिस

में सहभागिता अपना पूर्ण स्वाभिव्य प्राप्त किया जाता है,

निजीकरण का उद्देश्य: →

निजीकरण की अवधारणा का प्रादुर्भाव सार्वजनिक क्षेत्रों की असमर्थता के कारण हुआ।

निजीकरण में ऐसे उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य भी निहित है जिनको प्राप्त करना वरिष्ठ औद्योगिक युग में प्रत्येक विकासशील राष्ट्र के लिए अनिवार्य हो गया है।

निजीकरण के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं: —

1. राष्ट्र का हीन गति से आर्थिक विकास करना।
 2. रणनीतिक धातुओं को काम करना।
 3. उपक्रमों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना।
 4. वित्तियोग पर पर्याप्त उत्तिदान प्राप्त करना।
 5. लोक उपक्रमों की प्रतिप्रतितात्मक शक्ति में वृद्धि करना।
 6. औद्योगिक प्रवर्धन को गतिशील बनाना।
 7. उपक्रमों की उत्पादकता में वृद्धि करना।
 8. राष्ट्रीय संसाधनों का अधिकाधिक विद्वेदन करना।
 9. विस्तृत स्वाभिव्य एवं उत्तरदायित्व निश्चित करना।
 10. विदेशी पूंजी का अधिकाधिक उशल उपयोग करना।
 11. कार्य की दशाओं में सुधार करना।
 12. उच्च तकनीक का उपयोग सम्भव बनाकर सुव्यवस्था में सुधार करना।
 13. रोजगार सुविधाओं में वृद्धि करना।
 14. लोकसेवा में सरकारी स्वाभिव्य की समिति कर जनता की सहभागिता बढ़ाना।
- निजीकरण एवं उदारीकरण की नीति के कारण

भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी जा रही है जो कि भारत को विश्व के आर्थिक पहलू पर एक सशक्त रूप दिखाने में सहायक है।

निजीकरण द्वारा आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी उद्यमियों एवं विदेशी उद्योगपतियों की भागीदारी से औद्योगिक विकास में गतिशीलता आई है तथा औद्योगिक विकास की दर 5 गुना बढ़कर 8.5% हो गई है। निजीकरण एवं उदार आर्थिक नीति

के फलस्वरूप मुद्रास्फीति की दर नियंत्रित करने में मदद मिली है।

यद्यपि 1991 में 19% की गति 2013-14 के अंत में घटकर 6.7% रह गई है। बाद के वर्षों में मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होती रही। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आसमांश वृद्धि होने के कारण नवम्बर 2010 में जोड़ मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 8.1 प्रतिशत से बढ़कर 8.5 प्रतिशत हो गई।

फरवरी, 2015 में पुनः घटकर 5.37 प्रतिशत हो गई।